

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 29/19

1. बृजलाल पुत्र हरिया जाति मीना निवासी ग्राम रायसना तहसील नादौती जिला करीली

अपी०

बनाम



कंदारलाल  
गोपाललाल  
3. भरतलाल

पुत्रान घोरया जातियान मीना निवासीयान रायसना तहसील नादौती जिला करीली

4. तहसीलदार नादौती

रेस्प०

(अपील विरुद्ध निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास  
मु०न० 38/17 निर्णय व डिग्री दिनांक 23.5.18 )

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी० की और से श्री राधेश्याम वैष्णव
2. रेस्प० की और से श्री सी०एस०गुर्जर

निर्णय

दिनांक: 19.11.2020

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती के मु०न० 38/17 निर्णय व डिग्री दिनांक 23.5.18 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्प० संख्या 1 ता 3 ने एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 88,188, 207 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण के दादा ग्यारसा पुत्र मनफूल के कब्जे व बाड़े की भूमि खातेदारी की आराजी साबिक ख०न० 625 रकबा 3 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा थी, जो आज तक वादी के कब्जे में है। जिसमें वादीगण ने संयुक्त रूप से पशुओं को बांधने का बाड़ा बना रखा है व इस पर वादीगण के दादा ग्यारसा के समय से ही वादीगण के पिता घोरया व अब वादीगण के कब्जे में है। उक्त आराजी से किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई संबंध व वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। वादीगण की आराजी साबिक ख०न० 625 रकबा 3 विस्वा गैर मुमकिन बाड़ा के हाल सेटलमेंट ने नवीन ख०न० 2151 रकबा 0.92 है० किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया है। जिसमें अन्य लगते नया न० 614,618,620,622,626,628 ,617,619,621,623 व 627 भी नवीन ख०न० 2151 में सेटलमेंट ने समाहित कर नया न० 2151 कायम किया गया है। साबिक ख०न० 625 जो वादीगण के दादा ग्यारसा पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी रायसना की खातेदारी भूमि थी जो जमाबंदी सम्वत 2030-33 तक दर्ज है इस प्रकार वादीगण की पैतृक भूमि साबिक ख०न० 625 रकबा 3 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा को दौरान सेटलमेंट ने सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया व भूमिधारक राजस्थान सरकार को कायम कर दिया। यह काम

सेटलमेंट विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम किया है जबकि आज दिन तक वादीगण अपने दादा ग्यारसा के समय से ही उक्त पर काबिज है। इस भूमि से प्रतिवादी का कोई संबंध वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। जिसे वादीगण कानूनन दुरुस्त कराने का अधिकारी है। वादीगण आराजी हाल ख0न0 2151 मे से 3 विस्वा अपने कब्जे अनुसार कानूनन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है व इसी प्रकार अपने राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। वाकया दिनांक 22.5.17 का है कि वादीगण अपने बाडे मे अपने पशुओ की देखभाल कर रहे थे कि अचानक प्रतिवादी अपने अधिनस्थ कर्मचारियो के साथ मौके पर आया व कहा कि इस भूमि का भूमिधारक राजस्थान सरकार है। जिसका प्रतिनिधि मे लैण्ड होल्डर तहसीलदार नादौती हूँ व आप लोग इस भूमि को तुरन्त खाली कर दो अन्यथा मैं पुलिस प्रशासन लाकर तुम्हे यहाँ से बेदखल कर दूंगा। जब हमने कहा कि इस भूमि पर तो हमारे दादा के समय से ही हम काबिज है व यह हमारे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। दिनांक 25.5.17 को वादीगण ने तहसील मे आकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड देखा तो पता चला कि यह भूमि अब राज्य सरकार के खाते मे दर्ज है, जो दौराने सेटलमेंट हुई है। वादीगण ने पुराना रिकार्ड तलाश किया जो जमाबंदी सम्वत 2030-33 मे वादीगण के दादा ग्यारसा के नाम साबिक ख0न0 625 रकबा 3 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा दर्ज है। परन्तु अब इस साबिक ख0न0 सेटलमेंट विभाग ने नवीन ख0न0 2151 कायम कर आसपास के ख0न0 के साथ नवीन ख0न0 2151 मे समाहित कर दिया है। विनाय दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी दिनांक 22.5.17 बमुकाम रायसना प्रतिवादी द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने व दौराने सेटलमेंट गलत इन्द्राज होने से पैदा हुआ। इसलिए दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ जो अन्दर मियाद प्रस्तुत है। दावा बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती डिक्री किया जाकर हाल ख0न0 2151 रकबा 0.92 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी वाकेतन ग्राम रायसना तहसील नादौती जिला करौली मे से वादीगण के कब्जे मे 3 विस्वा व साबिक ख0न0 625 के अनुसार जो वादीगण के दादा के समय से ही चला आ रहा है प्रतिवादी की वर्तमान खातेदारी से हजफ कर उक्त ख0न0 2151 मे से नवीन नम्बर कायम कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्त किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांत वृजलाल द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र संलग्न कर अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। पुराने ख0न0 625 रकबा 3 विरवा किरम गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज था, उसके वर्तमान ख0न0 2151 रकबा 0.92 है0 बने है। जो कि गैर मुमकिन आबादी है। इस कारण उक्त भूमि ग्राम पंचायत की है। उक्त भूमि पर अपीलांट का 70 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर कब्जा है तथा अपीलांट की पत्नि मीरा को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पुख्ता मकान बनाने हेतु राशि स्वीकृत की गई थी तथा उसके कब्जे की भूमि पर मस्ट्रोल जारी की गई थी। इस प्रकार उक्त भूमि आबादी की होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने इसे अनदेखा कर प्रत्यार्थीगण की खातेदारी में दर्ज करने का निर्णय व डिक्री कर दिया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। रेस्प0 1 ता 3 मृतक ग्यारसा के किसी प्रकार के उत्तराधिकारी नहीं है ना ही मृतक ग्यारसा के वारिसान है। रेस्प0 ग्यारसा के वारिसान नहीं है। उन्होंने फर्जी वारिसान बनकर दावा गलत तथ्यों पर पेश किया गया है। इस प्रकार मृतक ग्यारसा के वारिसान रेस्प0 सिद्ध नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्प0 को ग्यारसा के वारिसान मानते हुए उक्त भूमि रेस्प0 की खातेदारी में दर्ज करने का गलत रूप से निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.5.18 को तनकीयात कायम कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियुक्त की गई थी, जिसमें ग्राम न्याय आपके द्वार कैंप ग्राम चिपवाड़ा में पेश होने हेतु पत्रावली में दिनांक 23.5.19 को पेशी नियुक्त की थी, जिसमें अपीलांट कोई सूचना नहीं दी तथा जानबूझकर रेस्प0 ने अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया है। जिसकी मौके पर जाँच नहीं की गई और चुपचाप गोपनीय तरीके से प्रतिवादी से मिलकर गलत निर्णय पारित किया है। जबकि आबादी भूमि की स्वामी ग्राम पंचायत है, जो उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी, लेकिन रेस्प0 संख्या 1 ता 3 ने अपीलांट व ग्राम पंचायत को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है। रेस्प0 गोपाल ने एक वाद पत्र न्यायालय सिविल न्यायालय श्रीमहावीरजी में अपीलांट की पत्नि तथा अपीलांट के पिता को पक्षकार बनाकर पेश कर रखा है जो लंबित है। रेस्प0 ने अधिनस्थ न्यायालय में वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था अपीलांधीन भूमि ख0न0 625 पर अपीलांट व उसके परिवार का पिछले 70 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में आज भी उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज है जो ग्राम पंचायत की भूमि है तथा उसी जगह अपीलांट का कब्जा मानते हुए अपीलांट की पत्नि को इन्द्रा आवास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र मानते हुए मकान आवास हेतु राशि स्वीकृत की है। जो तथ्य भी रेस्प0 की जानकारी में पूर्व से ही था। सिविल कोर्ट में लंबित वाद के इस तथ्य को रेस्प0 ने छिपाते हुए उक्त वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय से मिलकर गलत रूप से डिक्री करवा लिया जो निरस्त योग्य है। उक्त भूमि में अपीलांट का आवास बना हुआ है उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व गैर मुमकिन आबादी सही रूप से दर्ज की है। इस तथ्य को

अधिनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्त को इस निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी ना ही अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त पक्षकार था। अपीलान्त को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.04.19 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, तब अपीलान्त ने नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त के उपरान्त राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की। इस प्रकार अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अपीलान्त पेशकर निवेदन है कि आलोच्य निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय एस डी ओ नादौती दिनांक 23.05.18 अपारत फरमाया जावे।

15.11.20  
अधिकारी  
मालूम

रेस्पोंडेंट के विद्वान अधिवक्ता ने जबाब में तर्क दिया कि रेस्पोंडेंट/वादीगण के दादा ग्यारसा पुत्र मनफूल के कब्जे व बाड़े की भूमि खातेदारी की आराजी साबिक ख०न० 625 रकबा 3 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा थी, जो आज तक रेस्पोंडेंट के कब्जे में है। जिसमें रेस्पोंडेंट ने संयुक्त रूप से पशुओं को बांधने का बाड़ा बना रखा है व इस पर रेस्पोंडेंट के दादा ग्यारसा के समय से ही रेस्पोंडेंट के पिता घीस्या व अब रेस्पोंडेंट के कब्जे में है। यह भूमि ग्राम रायसना तहसील नादौती में स्थित है। उक्त आराजी से किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई संबंध व वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। रेस्पोंडेंट की आराजी साबिक ख०न० 625 रकबा 3 विस्वा गैर मुमकिन बाड़ा के हाल सेटलमेंट ने नवीन ख०न० 2151 रकबा 0.92 है० किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया है। जिसमें अन्य लगते नया न० 614,618,620,622,626,628,617,619,621,623 व 627 भी नवीन ख०न० 2151 में सेटलमेंट ने समाहित कर नया न० 2151 कायम किया गया है। साबिक ख०न० 625 जो रेस्पोंडेंट के दादा ग्यारसा पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी रायसना की खातेदारी भूमि थी जो जमाबंदी सम्बत 2030-33 तक दर्ज है इस प्रकार रेस्पोंडेंट की पैतृक भूमि साबिक ख०न० 625 रकबा 3 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा को दौरान सेटलमेंट ने सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया व भूमिधारक राजस्थान सरकार को कायम कर दिया। यह काम सेटलमेंट विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम किया है। जबकि आज दिन तक रेस्पोंडेंट अपने दादा ग्यारसा के समय से ही उक्त पर काबिज है। इस भूमि से अपीलान्त का कोई संबंध वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। रेस्पोंडेंट कानूनन दुरुस्त कराने का अधिकारी होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का पूर्ण रूप से विवेचन करने के उपरान्त ही अपीलान्त निर्णय पारित किया है। रेस्पोंडेंट/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पी डब्लू 1 ता पी डब्लू 4 के बयान कलम वद्ध कराये गये हैं जिन्होंने रेस्पोंडेंट को बाड़ा होना स्वीकार किया है तथा हमारे पूर्वजों के समय से कब्जा माना है। वादी/रेस्पोंडेंट द्वारा विवादित आराजीयात की जमाबंदी सम्बत 2030 से 2033 पेश की गई थी। जिसमें ख०न० 625 रकबा 3 विस्वा गैर मुमकिन बाड़ा की ग्यारसा पुत्र मनफूल के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलार्थी का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपील 20.05.2019 को पेश की है। यह

मियाद बहार है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावे।

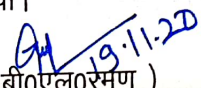


उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अद्योपान्त अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 23.05.2018 की अपील दिनांक 20.05.2019 को प्रस्तुत की है। प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 वाके ग्राम रायसना के खतौनी सं० 70 पर खसरा नम्बर 625 रकबा 3 बिस्वा ग्यारसा पुत्र मनफूल जाति मीना साकिन देह अंकित है। अन्य आराजीयों से सम्बन्धित नामान्तरकरण सं० 82 ग्यारसा पुत्र मनफूल के फौत हो जाने पर घीस्या पुत्र ग्यारसा के नाम उत्तराधिकारी के रूप में खोला गया है। इसके विपरीत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार नादौती द्वारा दिनांक 04.05.2018 का प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया है, जवाब में स्वीकार किया है, कि सैटलमेंट विभागीय कर्मचारीयों की सहवन से साबिक ख०नं० 625 को हाल ख०नं० 2151 रकबा 0.92 है० किस्म गैर मुमकीन आबादी में मर्ज कर दिया है। वादीगण के दादा ग्यारसा पुत्र मनफूल के समय से ही आज तक उक्त 3 बिस्वा भूमि सायलान के कब्जे में है। जिसमें वादीगण अपने पशु आदि बांधते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 को तनकीवार विवेचन पश्चात पारित किया गया है। इस निर्णय में कोई विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होती है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नादौती के मु०नं० 38/2017 निर्णय दिनांक 23.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( बी०एल०स्मरण )  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
राजस्व अपील अधिकारी  
सवाई माधोपुर